Government. The position regarding disbursement of the already sanctioned amount is being ascertained from the State Government.

Terminology Committee for mass media under bureau for promotion Urdu

7215. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a "Terminology Committee for Mass Media was formed under Bureau for Promotion of Urdu" decade ago;

(b) what are the names of its members;

(c) how many meetings were held in the past decade and how many words were coined; and

(d) when this Committee will submit its final report?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA). (a) to (d) Terminology Committee on Journalism and Mass Communication was constituted by the Standing Committee of Tarraqi-e-Urdu Board in its meeting held on 30th March, 1985. The statement of the present members is enclosed. The Committee has met thrice, finalised more than 500 terms and would complete the task by December, 1995.

Statement

List of Members of Mass Communication Terminology Committee.

1. Prof. S. M. Mehdi, Hyderabad.
2. Dr. M. R. Haq, New Delhi.
3. Shri Rizwani Ahmed, Patna.
4. Shri Raz Imtiaz, Bangalore.
5. Shri Mahmood Hashmi, New Delhi.
6. Shri M. R. Faruqi, New Delhi.
7. Dr. Khaliq Anjum, New Delhi.
8. Dr. Kamal Ahmad Siddiqi, Sahibabad (UP).
9. Shri Saeed Ahmad Malihabadi, Calcutta.
10. Shri Mazhar Imam, New Delhi.
11. Shri Mohan Chiraghi, New Delhi.
12. Shri J. P. Bhatnagar, (Coopted Member) New Delhi.

मध्य प्रदेश में "राजीव प्राथमिक शिक्षा मिशन"

7216. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए मध्य प्रदेश में "राजीव प्राथमिक शिक्षा मिशन" के अधीन कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ;

(ख) क्या इस मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 19 जिले चुने गए हैं और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए एक समिति गठित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके अतर्गत जिलों का चयन करने और इस समिति में सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए क्या प्रक्रिया/मापदण्ड अपनाए गए हैं ; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अतर्गत मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का भी चयन किया जाएगा, यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विकेन्द्रीकृत आयोजना की कार्यनीति को कार्यरूप प्रदान करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक एक नई पहल शुरू की गई है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश के 19 जिलों सहित 7 राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को राज्य स्तरीय स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के जरिए चलाया जा रहा है तथा मध्य प्रदेश में इस सोसायटी को नाम दिया गया है-राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। इस सोसायटी की एक महा परिषद् है जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं तथा एक कार्यकारिणी समिति है जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं। सोसायटी के उप-नियमों में महा-परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति दोनों में ही शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं और केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान है।

(ग) इन जिलों की पहचान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दोहरे मानदण्ड के आधार पर की गई है जो इस प्रकार है:—(क) राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता दर वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले, और/या (ख) ऐसे जिले जहां संपूर्ण साक्षरता अभियानों से प्रारंभिक शिक्षा के लिए मांग में बढ़ोत्तरी करने में सफलता हासिल हुई है।

(घ) अभी तक मध्य प्रदेश के और जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं है। यदि भविष्य में इसमें कोई विस्तार होगा तो वह जिन जिलों में यह कार्यक्रम पहले से शुरू किया गया है उनमें इसकी सफलता पर निर्भर करेगा।

Rewriting of history

7217. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has accepted the recommendations of the NCERT Review Committee on the communal rewriting of history in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh; and

(b) if so, what is the present status of the implementation of these recommendations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SHELJA): (a) and (b) The National Steering Committee on school textbook evaluation with its secretariat in the NCERT reviewed the school textbooks of Uttar Pradesh in 1992.

As per information received from the Committee's secretariat, the Commitee recommended the withdrawal of two History textbooks and two Mathematics text baoks which were prescribed for ciasses IX and X. This recommendation was based on the identification of material which was found to be objectionable in various lessons of these textbooks.

The withdrawal of these textbooks was recommended to the Government of Uttar Pradesh. As per information received from the State Government, they decided to withdraw the History textbooks and to exclude the objectionable material from the Mathematics books listed below. The text book in which objectionable lesson were discovered are:

1. High School Ithihas-Bhag-I
2. High School Ithihas-Bhag-II
3. High School Ganit-Bhag-I
4. High School Ganit-Bhag-II

The National Steering Committee has made no specific recommendations in respect of the school textbooks of Madhya Pradesh and Rajasthan.